NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 13 Nov , 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims	अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई
Page 02 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	क्रोमियम, निवासियों में पारा के उच्च स्तर; एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावित लोगों का नक्शा बनाने का निर्देश दिया
Page 03 Syllabus : GS 3 : Indian Economy	72.16% के साथ केरल रोजगार दर में चौथे स्थान पर है
Page 06 Syllabus : GS 3 : Environment	खराब मौसम से भारत नौवें स्थान पर सबसे ज्यादा प्रभावित: अध्ययन
Page 06 Syllabus : GS 2 : Social Justice	भारत में टीबी के मामलों में सालाना 21 फीसदी की गिरावट: डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 & 3 : Indian Polity and Economy	अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता जो भारत के विकास को बढ़ावा दे रही है

□□□□□ □□□□□□□

Page 01 : GS 3 : Indian Economy / Prelims

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) **द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति** अक्टूबर 2025 में 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर **तक गिर गई है, जो** जनवरी 2012 **में सीपीआई श्रृंखला शुरू होने के बाद से सबसे कम स्तर** है। सरकार इसका श्रेय **जीएसटी दरों में कटौती, अनुकूल आधार प्रभाव और** सब्जियों, फलों, तेलों और वसा जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट को देती है।

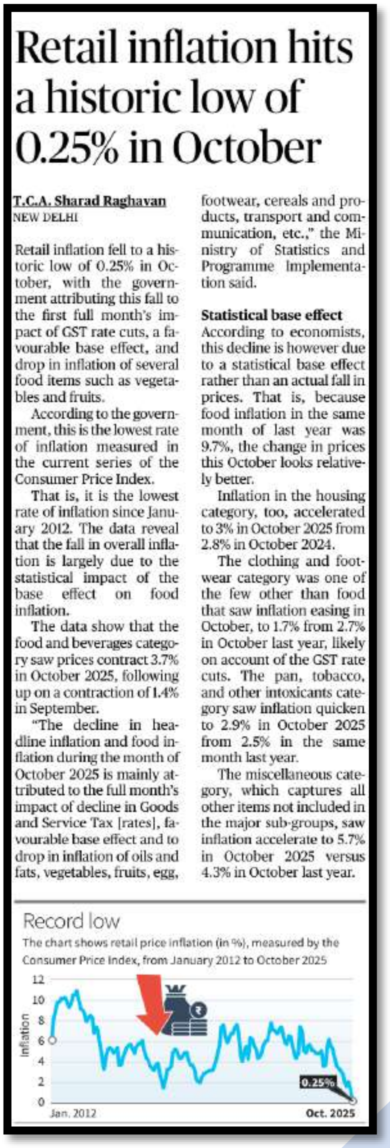

Retail inflation hits a historic low of 0.25% in October

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Retail inflation fell to a historic low of 0.25% in October, with the government attributing this fall to the first full month's impact of GST rate cuts, a favourable base effect, and drop in inflation of several food items such as vegetables and fruits.

According to the government, this is the lowest rate of inflation measured in the current series of the Consumer Price Index.

That is, it is the lowest rate of inflation since January 2012. The data reveal that the fall in overall inflation is largely due to the statistical impact of the base effect on food inflation.

The data show that the food and beverages category saw prices contract 3.7% in October 2025, following up on a contraction of 1.4% in September.

"The decline in headline inflation and food inflation during the month of October 2025 is mainly attributed to the full month's impact of decline in Goods and Service Tax [rates], favourable base effect and to drop in inflation of oils and fats, vegetables, fruits, egg, footwear, cereals and products, transport and communication, etc.," the Ministry of Statistics and Programme Implementation said.

Statistical base effect

According to economists, this decline is however due to a statistical base effect rather than an actual fall in prices. That is, because food inflation in the same month of last year was 9.7%, the change in prices this October looks relatively better.

Inflation in the housing category, too, accelerated to 3% in October 2025 from 2.8% in October 2024.

The clothing and footwear category was one of the few other than food that saw inflation easing in October, to 1.7% from 2.7% in October last year, likely on account of the GST rate cuts. The pan, tobacco, and other intoxicants category saw inflation quicken to 2.9% in October 2025 from 2.5% in the same month last year.

The miscellaneous category, which captures all other items not included in the major sub-groups, saw inflation accelerate to 5.7% in October 2025 versus 4.3% in October last year.

Record low

The chart shows retail price inflation (in %), measured by the Consumer Price Index, from January 2012 to October 2025

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब आरबीआई और नीति निर्माता मूल्य स्थिरता के साथ विकास पुनरुद्धार को संतुलित करने के लिए मुद्रास्फीति के रुझानों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं ।

मुख्य बिंदु

- **खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई):** 0.25% (ऐतिहासिक निम्न)।
- **खाद्य और पेय मुद्रास्फीति: अक्टूबर 2025 में** -3.7% **(सितंबर में -1.4%)** तक संकुचित हुई।
- **गिरावट के प्रमुख चालक:**
    - जीएसटी दरों में कटौती का पूरे महीने का असर।
    - **अनुकूल आधार प्रभाव** (अक्टूबर 2024 में उच्च 9.7% मुद्रास्फीति के साथ तुलना)।
    - सब्जियों, फलों, अंडे, तेल, अनाज, जूते, परिवहन और संचार **की कीमतों में गिरावट**।
- **आवास मुद्रास्फीति: बढ़कर** 3% **(पिछले वर्ष 2.8% से)** हो गई।
- **विविध श्रेणी:** 5.7% **तक बढ़ गया**, जो उच्च सेवा लागत को दर्शाता है।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

खुदरा मुद्रास्फीति क्या है?

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) **का उपयोग करके मापा जाता है**, जो घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को ट्रैक करता है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) **के तहत राष्ट्रीय** सांख्यिकी कार्यालय (NSO) **द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है**।

भारत में मुद्रास्फीति सूचकांकों के प्रकार:

एक. **सीपीआई (संयुक्त)** - ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को मापता है।
दो. **औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू)।**
तीन. **कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई (सीपीआई-एएल)।**
चार. **थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)** - थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है।

मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण:

- RBI अधिनियम, 1934 (संशोधित 2016) **के तहत**, **मौद्रिक नीति समिति (MPC) को** CPI मुद्रास्फीति को 4% ± 2% पर **रखने का अधिकार है**।
- 2% से नीचे लगातार मुद्रास्फीति मांग **में मंदी** और संभावित **अपस्फीतिकारी दबावों का संकेत दे सकती है**।

आधार प्रभाव:

- एक **सांख्यिकीय घटना** जहां पिछले वर्ष में एक उच्च (या निम्न) मुद्रास्फीति दर वर्तमान मुद्रास्फीति रीडिंग को प्रभावित करती है।
- एक **अनुकूल आधार प्रभाव** का मतलब है कि मुद्रास्फीति कम दिखाई देती है क्योंकि पिछले साल की कीमतें पहले से ही बहुत अधिक थीं।

आर्थिक निहितार्थ

पॉज़िटीव:

- **उपभोक्ता:** सस्ते भोजन और आवश्यक वस्तुओं से लाभ उठाएं।
- **आरबीआई पॉलिसी स्पेस:** यदि कम मुद्रास्फीति बनी रहती है तो **मौद्रिक सहजता** की अनुमति दे सकती है।
- **राजकोषीय प्रबंधन:** खाद्य और उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना।

चिंताओं:

- **आधार प्रभाव विरूपण:** कम मुद्रास्फीति सांख्यिकीय है, जरूरी नहीं कि वास्तविक हो।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था:** लंबे समय तक खाद्य कीमतों में अपस्फीति किसानों **की आय को नुकसान पहुंचा** सकती है।
- **कोर मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन):** अभी भी 5% से ऊपर, अंतर्निहित मूल्य कठोरता दिखा रहा है।
- **विकास लिंक: अल्ट्रा-लो मुद्रास्फीति** कमजोर मांग **और** सुस्त खपत **को प्रतिबिंबित कर सकती** है।

व्यापक संदर्भ

- भारत में आपूर्ति में व्यवधान, वैश्विक संघर्ष और कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण महामारी के बाद मुद्रास्फीति के **रुझान में उतार-चढ़ाव** देखा गया है।
- RBI ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संचयी वृद्धि के बाद 2024 में दर वृद्धि को रोक दिया था.
- वर्तमान रिकॉर्ड कम मुद्रास्फीति अस्थायी हो सकती **है, आधार** प्रभाव के फीके पड़ने के बाद **मध्यम पलटाव** की उम्मीद है।

समाप्ति

अक्टूबर 2025 में 0.25% **की रिकॉर्ड कम खुदरा मुद्रास्फीति** एक उल्लेखनीय सांख्यिकीय घटना है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह गहरी आर्थिक स्थिरता का संकेत हो। जबकि कीमतों में गिरावट उपभोक्ताओं को अल्पकालिक राहत प्रदान करती है, नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **कम मुद्रास्फीति ग्रामीण संकट या स्थिर मांग में तब्दील न हो**। भारत **की आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए एक** संतुलित दृष्टिकोण, विकास प्रोत्साहन **के साथ मूल्य** स्थिरता का संयोजन महत्वपूर्ण है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग करके मापा जाता है।

2. इसमें घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल हैं।

3. यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में हाल ही में रिकॉर्ड कम खुदरा मुद्रास्फीति वास्तविक आर्थिक सुधार की तुलना में एक सांख्यिकीय घटना को दर्शाती है। परखना। **(150 शब्द)**

Page 02 : GS 3 : Environment / Prelims

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी धातु संदूषण से प्रभावित सभी निवासियों की पहचान और नक्शा तैयार करे। यह संदूषण औद्योगिक अपशिष्ट डंपिंग से उत्पन्न होता है, विशेष रूप से चमड़े के कारखानों और कारखानों द्वारा, जिससे इन क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति होती है।

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□ □□□□□□□

High levels of chromium, mercury in residents; NGT directs U.P. govt. to map affected people

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The National Green Tribunal (NGT) has directed the Uttar Pradesh government to map the total number of people affected by heavy metal contamination, particularly chromium and mercury, in Kanpur Nagar, Kanpur, Fatehpur, and nearby areas of the State.

The Principal Bench of the NGT, comprising chairperson Prakash Shrivastava and expert member Afroz Ahmad, gave the order in a matter related to factories dumping chromium in Rania, Kanpur Dehat, Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, and nearby areas which has resulted in contamination of groundwater, depriving local people access to drinking water.

The NGT gave the order in a matter related to factories dumping chromium in some areas, resulting in contamination of groundwater. FILE PHOTO

"The above chart reflects that in high percentage of persons presence of Chromium above standard level has been detected and even persons with Mercury above standard level have been found (*sic*)," stated the order dated November 7.

As per the chart mentioned in the order, 95.7% of the 514 people tested in Kanpur Nagar had chromium above the standard level in their blood samples, and the figure stood at 71.9% for Kanpur Dehat (214 people tested) and 85.96% for Fatehpur (171 people tested).

"The State authorities, especially the Chief Secretary, Uttar Pradesh, and Secretary, Health, Govt. of U.P. are directed to provide a timeline within two weeks in respect of the steps that will be taken by the State authorities to complete the process of mapping the entire area and find out the affected villages/ULBs [urban local bodies]/districts," the order said.

"They will also disclose the approximate number of the affected persons, the medical facilities available at the District/ULB/Village level including the health centers, doctors, paramedical staff available in those health centres, the facilities available in those health centres and the nearby labs and distance from that lab for carrying out the blood and other sample analysis," the order stated.

"The mapping will include food chain contamination, surface water and groundwater contamination, and air contamination analysis. The timeline will also be given for fully implementing the 22 recommendations which have been noted in the order dated 01.07.2025," the order said.

महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रभावित क्षेत्र: रानिया (कानपुर देहात), राखी मंडी (कानपुर नगर), फतेहपुर और आसपास के क्षेत्र।
- पहचाने गए संदूषक: हेक्सावलेंट क्रोमियम (Cr^{6+}) और पारा (Hg) - दोनों अत्यधिक जहरीली भारी धातुएं।
- संदूषण की सीमा:
    - कानपुर नगर: जांच किए गए 514 लोगों में से 95.7% में क्रोमियम का स्तर मानक से अधिक था।
    - कानपुर देहात: 71.9% (214 परीक्षणों में से)।
    - फतेहपुर: 85.9% (171 टेस्ट में से)।
- एनजीटी बेंच: न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और डॉ. अफरोज अहमद (विशेषज्ञ सदस्य)।

- राज्य को निर्देश:
    - सभी प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की पूरी मैपिंग।
    - स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (डॉक्टरों, प्रयोगशालाओं, स्वास्थ्य केंद्रों) पर विवरण प्रदान करें।
    - खाद्य श्रृंखला, सतही जल और वायु संदूषण विश्लेषण शामिल करें।
    - 22 उपचारात्मक सिफारिशों को लागू करने के लिए समयसीमा जमा करें (पहले का आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2025)।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

NGT के बारे में:

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत 2010 में स्थापित।
- उद्देश्य: पर्यावरण संरक्षण और वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना।
- शक्तियों:
    - पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करता है।
    - प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करता है।
    - प्राकृतिक न्याय और सतत विकास के सिद्धांतों (एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत) द्वारा निर्देशित।

क्रोमियम और पारा के बारे में:

- क्रोमियम (हेक्सावलेंट Cr^{6+}): टैनिंग उद्योगों में उपयोग किया जाता है, अत्यधिक कार्सिनोजेनिक, फेफड़ों के कैंसर, यकृत और गुर्दे की क्षति और त्वचा के अल्सर का कारण बनता है।
- पारा (एचजी): इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है, खाद्य श्रृंखला में जैव संचय करता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार होते हैं।
- स्रोत: टेनरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कपड़ा रंगाई, रासायनिक संयंत्र।
- पर्यावरणीय प्रभाव: भूजल और मिट्टी को दूषित करता है, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, मनुष्यों, पशुधन और फसलों को प्रभावित करता है।

मुद्दे और निहितार्थ

(a) स्वास्थ्य प्रभाव

- लंबे समय तक संपर्क में रहने से बच्चों में कैंसर, यकृत/गुर्दे की विफलता, तंत्रिका संबंधी विकार और विकास संबंधी दोष होते हैं।
- जल प्रदूषण समुदायों को पीने और सिंचाई के लिए असुरक्षित स्रोतों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है।

(b) पर्यावरणीय प्रभाव

- भारी धातुएं फसलों और जलीय जीवों में जैव संचय करती हैं, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन होता है।
- सतह और भूजल संदूषण औद्योगिक क्षेत्रों से परे फैलता है।

(c) शासन और जवाबदेही

- यह मुद्दा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे पर्यावरण कानूनों के कमजोर प्रवर्तन को उजागर करता है।
- यह खराब औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की विफलता को दर्शाता है।
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता।

व्यापक संदर्भ और सरकार की प्रतिक्रिया

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) औद्योगिक बहिस्रावों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन समन्वय अंतराल बना हुआ है।
- मानचित्रण पर एनजीटी का जोर तदर्थ प्रदूषण नियंत्रण से डेटा-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में बदलाव का संकेत देता है।
- खाद्य श्रृंखला संदूषण को शामिल करने का निर्देश समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधों की मान्यता को दर्शाता है।

समाप्ति

उत्तर प्रदेश में क्रोमियम और पारा संदूषण की मैपिंग पर एनजीटी का आदेश पर्यावरण न्याय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, वास्तविक परिवर्तन कठोर कार्यान्वयन, सख्त औद्योगिक विनियमन और सामुदायिक जागरूकता पर निर्भर करेगा। यह घटना एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बिना अनियंत्रित औद्योगीकरण मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक सुरक्षा दोनों को खतरे में डाल सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में क्रोमियम और पारा संदूषण के मानचित्रण के लिए खबरों में था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था?

(A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(B) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

(C) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(D) जैव विविधता अधिनियम, 2002

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : पानी में भारी धातु संदूषण के प्रमुख स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? ऐसे प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाएं। **(150 शब्द)**

Page : 03 : GS 3 : Indian Economy

केरल ने इंडिया स्किल्स रिपोर्ट (ISR) 2026 में प्रभावशाली 72.16% रोजगार दर के साथ भारतीय राज्यों के बीच रोजगार दर में चौथे स्थान पर रहकर एक बार फिर अपने मजबूत मानव पूंजी आधार का प्रदर्शन किया है। केवल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने बेहतर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट में केरल के लिंग-समावेशी कार्यबल और क्षेत्रीय कौशल तत्परता, विशेष रूप से बीएफएसआई, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों में प्रकाश डाला गया है।

At 72.16%, Kerala stands fourth in employability rate

Sarath Babu George
THIRUVANANTHAPURAM

Kerala has reaffirmed its strong position in the country's employability landscape by emerging fourth among the top-performing States in the India Skills Report 2026. The State recorded an employability rate of 72.16% – only Uttar Pradesh, Maharashtra, and Karnataka have better rates.

The State also figures among the top-10 preferred States for women professionals, with the report underlining Kerala's gender-inclusive labour ecosystem.

The report has been published by global education and talent solutions organisation ETS in association with various agencies, including the All India Council for Technical Education, Confederation of Indian Industry, and the Association of Indian Universities.

Job readiness

Nationally, overall employability has risen to 56.35%, up from 54.81% last year, with more than half of India's graduates scoring above 60% in the Global Employability Test (GET) conducted to compile the report. Kerala figures prominently in both State and city-level rankings, reflecting a consistent rise in job readiness and sector-specific skill alignment.

Among the top performing cities, Kochi ranks fourth, ahead of major metros such as Delhi and Hyderabad, with an average employability score of 76.56%. The report identifies Tier-2 cities such as Kochi and Lucknow to be emerging as strong talent hubs, narrowing the urban-rural skill gap.

Women's employability in the country has seen a remarkable rise to 54%, surpassing men (51.5%) for the first time. Kerala, along with Uttar Pradesh and Telangana, leads this shift by reporting strong female participation in banking, financial services and insurance sector (BFSI), health care and education sectors.

मुख्य निष्कर्ष

□□□□□ □□□□□□□

सूचक	केरल का प्रदर्शन/राष्ट्रीय डेटा
रोजगार दर	72.16% (राज्यों में चौथा)
राष्ट्रीय रोजगार (कुल मिलाकर)	56.35% (पिछले वर्ष के 54.81% से ऊपर)
शीर्ष राज्य	उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल
शीर्ष शहर	कोच्चि राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर (76.56% रोजगार)
महिलाओं की रोजगार क्षमता	54% (पुरुषों के 51.5% से अधिक) - पहली बार
केरल में रोजगार क्षमता को बढ़ा रहे क्षेत्र	बीएफएसआई, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा
महिला पेशेवरों के लिए पसंदीदा राज्य	शीर्ष 10 में केरल

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 को संयुक्त रूप से ईटीएस (एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस), एआईसीटीई, सीआईआई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) द्वारा तैयार किया गया था। यह ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट (जीईटी) में प्रदर्शन पर आधारित है, जो स्नातकों की नौकरी की तैयारी और मुख्य कौशल का मूल्यांकन करता है।

स्थैतिक पृष्ठभूमि

रोजगार क्या है?

- रोजगार योग्यता किसी व्यक्ति की कौशल के आधार पर रोजगार प्राप्त करने और बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करती है, जो उनके कौशल, ज्ञान और अनुकूलनशीलता पर आधारित होती है।
- यह रोजगार दर से अलग है - रोजगार की तत्परता को मापता है, वास्तविक नौकरी की उपलब्धता नहीं।

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट (ISR) के बारे में:

- व्हीबॉक्स, एआईसीटीई, सीआईआई, एआईयू और यूएनडीपी इंडिया (और अब ईटीएस) द्वारा एक वार्षिक संयुक्त पहल।
- इसका उद्देश्य भारतीय राज्यों में कौशल के रुझान, रोजगार के स्तर और उद्योग की मांग का मानचित्रण करना है।
- ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट (जीईटी) के माध्यम से देश भर में 300,000 से अधिक छात्रों का परीक्षण करता है।

कौशल विकास पर सरकारी ढांचा:

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (2015) - एमएसडीई के तहत छाता ढांचा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) – अल्पकालिक कौशल प्रमाणन।
- स्किल इंडिया अभियान - 400 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।
- आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (एएसईईएम) प्लेटफॉर्म - श्रम बाजार में मांग-आपूर्ति असंतुलन को पाटता है।

विश्लेषण और निहितार्थ

(a) केरल के लिए

- यह विशेष रूप से उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में मजबूत शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है।
- लैंगिक समावेशिता और सामाजिक विकास संकेतक एक संतुलित कार्यबल में योगदान करते हैं।
- कोच्चि जैसे टियर-2 शहरों का नए टैलेंट हब के रूप में उभरने से मेट्रो पर निर्भरता कम हो गई है।

(b) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

- रोजगार क्षमता में समग्र वृद्धि (54.81% से 56.35%) शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर संरेखण का संकेत देती है।
- हालांकि, 56% की दर का मतलब यह भी है कि भारत के लगभग आधे स्नातक कम कुशल या बेरोजगार बने हुए हैं, जो कौशल अंतर की चुनौती को उजागर करता है।

(c) महिला सशक्तिकरण

- रोजगार के मामले में पुरुषों से आगे निकलने वाली महिलाओं का भारत की श्रम गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
- बीएफएसआई, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्र महिला पेशेवरों के लिए सुरक्षित, समावेशी और लचीले अवसरों को सक्षम कर रहे हैं।

चुनौतियों

- कौशल-उद्योग बेमेल: कई स्नातकों में नियोक्ताओं द्वारा मांग किए गए डोमेन-विशिष्ट और डिजिटल कौशल की कमी होती है।
- क्षेत्रीय असमानताएँ: जबकि केरल और दक्षिणी राज्य सबसे आगे हैं, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र पीछे हैं।
- बेरोजगारी: उच्च रोजगार हमेशा उच्च-गुणवत्ता या पर्याप्त भुगतान वाली नौकरियों में तब्दील नहीं होता है।
- प्रतिभा पलायन: केरल जैसे राज्यों से महानगरों या विदेशों में पलायन करने वाले कुशल युवा।

□□□□□ □□□□□□

समाप्ति

केरल की 72.16 प्रतिशत रोजगार दर और बढ़ती महिला भागीदारी मानव संसाधन विकास में एक आदर्श राज्य के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करती है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता और उद्योग की मांग के साथ कौशल संरेखण भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, शहरी-ग्रामीण और कौशल अंतर को पाटना, सार्थक रोजगार सुनिश्चित करना और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को बनाए रखना वास्तव में कुशल भारत प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण अगला कदम है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 भारत के रोजगार परिदृश्य में प्रगति और लगातार चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डालती है। केरल के प्रदर्शन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□□

Page 06 : GS 3 : Environment

बॉन स्थित पर्यावरण और विकास संगठन जर्मनवॉच द्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI) 2026 भारत को 1995 और 2024 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से विश्व स्तर पर नौवें सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में स्थान देता है। यह रिपोर्ट ब्राजील के बेलेम में COP30 के दौरान जारी की गई थी, जिसमें जलवायु-प्रेरित आपदाओं के प्रति विकासशील देशों की बढ़ती संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया था।

मुख्य निष्कर्ष

सूचक	डेटा/निष्कर्ष
कवर की गई अवधि	1995–2024
चरम घटनाएं दर्ज की गईं	9,700 से अधिक
वैश्विक मानव टोल	8.32 लाख मौतें
प्रभावित लोग	5.7 बिलियन
आर्थिक नुकसान	$ 4.5 ट्रिलियन से अधिक (मुद्रास्फीति-समायोजित)
भारत की रैंक	9वां सबसे अधिक प्रभावित देश
शीर्ष प्रभावित देश	हैती, फिलीपींस, भारत, पाकिस्तान, मोजाम्बिक, आदि।
भारत में प्रमुख आपदाएँ	बाढ़, चक्रवात (अम्फान, फानी, तौकते), सूखा और गंभीर लू
रिपोर्ट जारी की गई	COP30, बेलेम (ब्राजील)
द्वारा प्रकाशित	जर्मनवॉच - वैश्विक समानता और जलवायु न्याय की वकालत करता है

स्थैतिक पृष्ठभूमि

जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI) के बारे में:

- जर्मनवॉच की एक वार्षिक रिपोर्ट ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके देशों पर चरम मौसम के प्रभावों का आकलन करती है।
- संकेतकों के आधार पर जैसे:
    - एक. मौसम संबंधी घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या।
    - दो. प्रति 100,000 निवासियों पर मौतें।
    - तीन. आर्थिक नुकसान (USD में)।
    - चार. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हानि।
- सीआरआई वास्तविक दुनिया के जोखिम और जलवायु चरम सीमाओं के प्रति भेद्यता को दर्शाता है।

जर्मनवॉच के बारे में:

- 1991 में स्थापित, इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है।
- फोकस क्षेत्र: जलवायु नीति, सतत विकास और वैश्विक इक्विटी।

- जलवायु न्याय की वकालत करने वाले UNFCCC प्रक्रियाओं और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर काम करता है।

विश्लेषण: भारत अत्यधिक असुरक्षित क्यों है

a. भौगोलिक एक्सपोजर

- भारत की विशाल तटरेखा (7,500 किमी) और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र इसे चक्रवात, बाढ़, हिमनदों के पिघलने और भूस्खलन के लिए प्रवण बनाते हैं।
- मानसून की अनियमितताओं के कारण बार-बार सूखा और बाढ़ आती है।

बी। **सामाजिक आर्थिक कारक**

- उच्च जनसंख्या घनत्व और कृषि पर निर्भरता भेद्यता को बढ़ाती है।
- बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अनौपचारिक बस्तियां और खराब आपदा लचीलापन प्रभाव को बदतर बना देता है।

c. जलवायु रुझान

- हीटवेव की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता, 2024-25 सबसे गर्म वर्षों में से एक दर्ज किया गया।
- वर्षा के पैटर्न में बदलाव से खाद्य सुरक्षा और पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।
- अनियोजित शहरीकरण के कारण शहरी बाढ़ (मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु) में वृद्धि।

डी। **आर्थिक परिणाम**

- आपदाओं के कारण आवर्ती बुनियादी ढांचे को नुकसान, आजीविका का नुकसान और स्वास्थ्य आपात स्थिति होती है।
- जलवायु संबंधी आपदाओं (नीति आयोग का अनुमान) के कारण भारत सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% खो देता है।

नीति और संस्थागत ढांचा

रूपरेखा/पहल	**वस्तुनिष्ठ**
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी, 2008)	सौर ऊर्जा, जल, कृषि आदि पर आठ राष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा मंत्रालय में कार्य किया जा रहा है।
जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी)	राज्य स्तरीय अनुकूलन और शमन योजनाएं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)	जलवायु आपदाओं के लिए संस्थागत प्रतिक्रिया।

India ninth worst affected by extreme weather: study

Purnima Sah
MUMBAI

A new report, Climate Risk Index (CRI) 2026, published by Germanwatch, released at COP30 in Belém on Tuesday evening, finds that more than 832,000 people died, nearly 5.7 billion were affected, and economic losses exceeded $4.5 trillion (inflation-adjusted) from over 9,700 extreme weather events between 1995 and 2024.

Germanwatch is a Bonn-based environmental and development organisation that advocates for global equity and sustainability in climate policy.

India ranks ninth among the countries most affected during this period, facing recurring floods, cyclones, droughts, and increasingly severe heatwaves. "Countries such as Haiti, the Philippines, and India - all of which are among the ten most affected - face particular challenges. They are hit by floods, heatwaves, or storms so regularly that entire regions can hardly recover from the impacts until the next event strikes," said Vera Künzel, senior advisor on climate change adaptation and human rights at Germanwatch.

□□□□□ □□□□□□□

रूपरेखा/पहल	वस्तुनिष्ठ
आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI)	बुनियादी ढांचे में लचीलापन बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल।
पंचामृत लक्ष्य (COP26)	2070 तक नेट जीरो; 2030 तक 50% नवीकरणीय क्षमता।

इनके बावजूद, कार्यान्वयन अंतराल और अपर्याप्त अनुकूलन वित्त राज्य और स्थानीय स्तरों पर बना हुआ है।

वैश्विक और नैतिक आयाम

- रिपोर्ट जलवायु अन्याय को रेखांकित करती है – भारत जैसे विकासशील देश, जो वैश्विक उत्सर्जन में बहुत कम योगदान देते हैं, जलवायु प्रभावों से असमान रूप से पीड़ित हैं।
- हानि और क्षति निधि के संचालन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला (COP28 में सहमत)।
- सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) के तहत जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारत के तर्क को मजबूत करता है।

समाप्ति

जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 इस बात की याद दिलाता है कि भारत के विकासात्मक लाभ जलवायु के झटकों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। बार-बार बाढ़, हीटवेव और चक्रवात राष्ट्रीय योजना, शहरी डिजाइन और कृषि रणनीति में जलवायु लचीलेपन को एकीकृत करने की तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं। जैसा कि भारत सतत विकास पर जोर दे रहा है, जलवायु अनुकूलन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और वैश्विक जलवायु न्याय तंत्र को इसके पर्यावरण और आर्थिक एजेंडे का मूल बनाना चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

Ques चरम मौसम की घटनाओं के लिए भारत का बार-बार संपर्क विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए गहराते जलवायु जोखिम को दर्शाता है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के निष्कर्षों के संदर्भ में चर्चा करें। **(250 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□□

Page 06 : GS 2 : Social Justice

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत ने तपेदिक (टीबी) की घटनाओं में 21% की गिरावट हासिल की है – 237 प्रति लाख जनसंख्या (2015) से 187 प्रति लाख (2024) तक। यह गिरावट वैश्विक औसत (12%) से लगभग दोगुनी है, जो भारत को टीबी नियंत्रण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उच्च बोझ वाले देशों में से एक के रूप में स्थापित करती है।

यह प्रगति टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत की मजबूत प्रतिबद्धता, नवीन केस-फाइंडिंग तंत्र और समुदाय-संचालित और प्रौद्योगिकी-सक्षम रणनीतियों के माध्यम से विस्तारित उपचार कवरेज को दर्शाती है।

Tuberculosis incidence falling in India by 21% a year: WHO report

Bindu Shajan Perappadan
NEW DELHI

India's tuberculosis (TB) incidence, with new cases emerging every year, fell by 21% – from 237 TB cases per lakh population in 2015 to 187 per lakh population in 2024 – almost double the pace of decline observed globally, at 12%, according to the World Health Organization (WHO) Global TB Report, 2025, the Union Health Ministry said in a release issued on Wednesday. This was one of the highest declines in TB incidence globally, outpacing reductions noted among other high-burden countries.

"India's innovative case finding approach, driven by the swift uptake of newer technologies, decentralisation of services, and large-scale community mobilisation, has led to the country's treatment coverage to surge to over 92% in 2024, from 53% in 2015 – with 26.18 lakh TB patients being diagnosed in 2024, out of an estimated incidence of 27 lakh cases," the release said.

India leads global TB fight

India records one of the world's steepest tuberculosis declines, doubling global progress through innovation and outreach

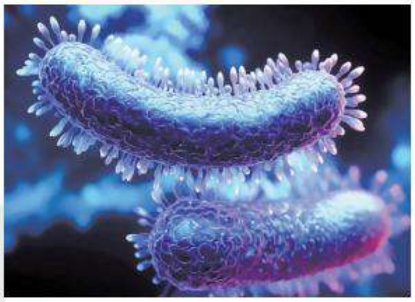

- TB incidence fell 21% (2015–2024), from 237 to 187 cases per lakh.
- Treatment coverage rose from 53% (2015) to 92% (2024)
- 26.18 lakh diagnosed out of 27 lakh estimated cases
- The number of missing cases reduced from from 15 lakh (2015) to <1 lakh (2024)
- The treatment success rate in India was about 90%, against the global average of 88%
- TB mortality declined from 28 deaths per lakh to 21 deaths per lakh (2015–2024)

The Ministry said this had helped reduce the number of "missing cases" – those who had TB but were not reported to the programme – from an estimated 15 lakh in 2015 to less than one lakh in 2024.

Also, there is no significant increase in the number of multidrug-resistant (MDR) TB patients in the country, adding that treatment success rate under the TB Mukt Bharat Abhiyan increases to 90%, ahead of the global treatment success rate of 88%.

India's TB mortality rate has also decreased from 28 per lakh population in 2015 to 21 per lakh population in 2024, reflecting significant progress in reducing deaths due to TB.

Since its launch in December 2024, India's flagship TB elimination mission, the TB Mukt Bharat Abhiyan, has achieved extensive reach, screening over 19 crore vulnerable individuals for TB across the country, leading to the detection of over 24.5 lakh TB patients, including 8.61 lakh asymptomatic TB cases, the report said.

मुख्य निष्कर्ष

सूचक	2015	2024	जारी रहना
टीबी की घटना	237 प्रति लाख	187 प्रति लाख	↓ 21%
वैश्विक औसत गिरावट	–	–	↓ 12%

□□□□□ □□□□□□□

सूचक	2015	2024	जारी रहना
उपचार कवरेज	53%	92%	बड़ा सुधार
रोगियों का निदान किया गया	–	26.18 लाख (27 लाख अनुमानित में से)	97% रिपोर्टिंग
लापता मामले	15 लाख	< 1 लाख	भारी कमी
उपचार की सफलता दर	–	90%	वैश्विक औसत: 88%
मृत्यु दर	28 प्रति लाख	21 प्रति लाख	↓ 25%
एमडीआर-टीबी मामले	–	स्थिर (कोई बड़ी वृद्धि नहीं)	नियंत्रित प्रसार

स्थैतिक एकीकरण

तपेदिक (टीबी) क्या है?

- माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस *के कारण होने वाला एक संचारी जीवाणु रोग*, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है लेकिन अन्य अंगों में फैल सकता है।
- संचरण का तरीका: वायुजनित - एक संक्रमित व्यक्ति की बूंदों के माध्यम से।
- लक्षण: खांसी >2 सप्ताह, बुखार, वजन घटाने, रात को पसीना।

वैश्विक और राष्ट्रीय ढांचे

ढांचा	सालों	वस्तुनिष्ठ
टीबी रणनीति को समाप्त करने वाली डब्ल्यूएचओ (2015-2035)	2015	2035 तक टीबी की घटनाओं को 90% और मौतों को 95% तक कम करना (आधार: 2015)।
टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (भारत)	2017–2025	वैश्विक SDG लक्ष्य (2030) से पांच साल पहले 2025 तक भारत में TB को खत्म करना।
एसडीजी लक्ष्य 3.3	–	2030 तक एड्स, टीबी, मलेरिया और अन्य संचारी रोगों की महामारी को समाप्त करना।

सरकारी पहल और नवाचार

(a) टीबी मुक्त भारत अभियान (2024–)

- 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लिए भारत का प्रमुख मिशन।
- स्क्रीनिंग: 19 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई, 24.5 लाख रोगियों का पता चला (8.61 लाख स्पर्शोन्मुख सहित)।
- सामुदायिक जुड़ाव, डिजिटल उपकरण और निजी क्षेत्र के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करें।

(b) प्रमुख घटक

- नि-क्षय पोर्टल: वास्तविक समय में केस ट्रैकिंग, उपचार पालन और डेटा प्रबंधन के लिए।
- नि-क्षय मित्र पहल: नागरिकों और संगठनों को पोषण और भावनात्मक समर्थन के लिए टीबी रोगियों को "गोद लेने" में सक्षम बनाता है।
- सेवाओं का विकेंद्रीकरण: जिला/ब्लॉक स्तर पर निदान और उपचार सुविधाएं।
- नए डायग्नोस्टिक्स: रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट (CBNAAT, TrueNat), डिजिटल एक्स-रे, एआई-आधारित रीडिंग टूल।
- पोषण सहायता: टीबी रोगियों के लिए नि-क्षय पोषण योजना के माध्यम से ₹1,000/माह।

भारत की उपलब्धि का महत्व

- वैश्विक नेतृत्व: कुछ उच्च-बोझ वाले देशों में से जो निरंतर दोहरे अंकों की गिरावट दिखा रहे हैं।
- स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना: प्रौद्योगिकी, सामुदायिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिबद्धता के प्रभावी एकीकरण को प्रदर्शित करता है।
- "लापता मामलों" में कमी: बेहतर रिपोर्टिंग और निगरानी को इंगित करता है।
- आर्थिक प्रभाव: टीबी उन्मूलन उच्च उत्पादकता का समर्थन करता है; अगर टीबी को रोका नहीं गया तो भारत को अनुमानित $ 340 बिलियन (2019-2030) का नुकसान होता है।

आगे की चुनौतियाँ

- दवा प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर/एक्सडीआर): हालांकि स्थिर है, यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है।
- शहरी मलिन बस्तियां और प्रवासी: दुर्गम आबादी को अभी भी निदान और पालन के मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
- कलंक और जागरूकता: सामाजिक वर्जनाएं समय पर परीक्षण और उपचार में बाधा डालती हैं।
- टीबी के बाद रिकवरी: कई ठीक हुए रोगियों को लंबे समय तक श्वसन संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।
- वित्त पोषण और स्थिरता: पूर्ण उन्मूलन के लिए 2025 के बाद भी निरंतर निवेश की आवश्यकता है।

समाप्ति

जैसा कि डब्ल्यूएचओ द्वारा रिपोर्ट किया गया है, टीबी के मामलों में भारत की उल्लेखनीय 21% वार्षिक गिरावट, देश की मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता और नवीन सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों को रेखांकित करती है। हालांकि यह प्रगति भारत को वैश्विक लक्ष्यों से पहले टीबी को खत्म करने की राह पर रखती है, लेकिन दवा प्रतिरोध, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता जैसी चुनौतियों का अभी भी समाधान किया जाना चाहिए। 2025 तक टीबी मुक्त भारत को प्राप्त करने के लिए निरंतर वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी एकीकरण और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है - जो रोग उन्मूलन में दुनिया के लिए एक मॉडल है।

UPSC Prelims Practice Question
प्रश्न: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2015 और 2024 के बीच भारत की टीबी घटनाओं में 21% की गिरावट आई है। 2. टीबी के मामलों में गिरावट की भारत की दर वैश्विक औसत से धीमी है। 3. टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत की उपचार सफलता दर वैश्विक औसत से अधिक है। **उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?** (A) केवल 1 (B) केवल 1 और 3 (C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2 और 3 **उत्तर : b)**
UPSC Mains Practice Question
प्रश्न: टीबी की घटनाओं को कम करने में भारत की सफलता प्रौद्योगिकी-संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के महत्व पर प्रकाश डालती है। चर्चा करना। **(250 शब्द)**

Page : 08 Editorial Analysis

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Inter-State rivalry that is fuelling India's growth

Duvvuri Subbarao

is a former Governor, Reserve Bank of India (2008-2013)

Last month, when Google unveiled its plans for its largest Artificial Intelligence (AI) data centre outside of California, U.S., in Andhra Pradesh, Chief Minister N. Chandrababu Naidu gleefully claimed bragging rights – a global tech titan choosing his State for a marquee investment over regional rivals such as Tamil Nadu and Karnataka. The jubilation in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, could be heard across State borders. In Tamil Nadu, a former All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Minister chided the Dravida Munnetra Kazhagam-led Stalin government for failing to woo Google, although it is headed by a true-blue Tamil. Across another border, a Karnataka Minister suggested, with barely concealed envy, that Andhra Pradesh had lured Google with "extravagant subsidies".

Strip away the politics, though, and what you see is something profoundly healthy – competition among States for investment – a potentially powerful engine for growth. For the first time in decades, Chief Ministers are not queuing in Delhi's corridors of power, but are in boardrooms of multinationals and corporate conclaves, persuading investors that India's best destination is their State.

Central patronage to competitive federalism

To appreciate this shift, cast your mind back to pre-1991 India. For four decades after Independence, capital investment was largely a political decision made in New Delhi. The "commanding heights" of the economy were occupied by bureaucrats who dispensed patronage through licences, permits and quotas. The country's industrial geography was determined by political calculation rather than market forces. The Centre decided what should be produced, how much should be produced, and, crucially, where it should be produced.

States, on their part, vied for investment not by wooing potential investors but by wooing politicians in Delhi.

The reforms in 1991 changed that. By dismantling industrial licensing and opening India to trade and investment, liberalisation shifted power – at least partly – from the Centre to the States. One of the unstated hopes then was that economic freedom would unleash competition among States to attract investors through better infrastructure, governance and policy stability.

That transformation took time. For much of the next two decades, investment decisions remained Delhi-centric. Public enterprises continued to dominate and State bureaucracies were slow to adapt to a more entrepreneurial era.

The promise of reforms is now being realised. The rise of competitive federalism has been one of the quiet revolutions of the past decade. States today compete not just with land, concessional utilities and tax breaks, but with reliability – predictable policy, faster clearances, skilled labour and good governance.

Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka vying for global tech mandates – from Google to Micron – is evidence of a maturing federal economy. When Foxconn debated where to locate its electronics facilities, States from Maharashtra to Tamil Nadu made pitches at the highest level. When Vedanta and Foxconn announced their semiconductor joint venture, both Maharashtra and Gujarat lobbied intensely, with Gujarat eventually breasting the tape. The tussle between Tamil Nadu and Telangana over electric vehicle (EV) manufacturing hubs underscored how investment courting has become a professional, high-stakes exercise.

Experience in other federations

India is not unique in this. Healthy subnational competition is a defining feature of all successful federations.

In the United States, when Amazon announced plans for a second headquarters, over 200 cities submitted proposals offering tax breaks, infrastructure support and workforce commitments. Although critics called it a subsidy race, it forced cities to improve governance and transparency. Many of the proposals later formed blueprints for urban renewal projects even where Amazon did not invest.

In Germany, the federal Länder (States) compete to attract high-tech industries. Bavaria's transformation into an innovation hub – home to BMW, Siemens and a cluster of "Mittelstand" firms – owes much to policy agility that other German States have since emulated.

Australia and Canada show similar patterns. Australian States compete to attract mining, clean energy and education investments, while Canadian provinces such as Ontario and British Columbia vie for technology and film production hubs. The result in all these cases is a virtuous cycle: competition that spurs innovation, efficiency and reform.

India's own States are now entering that league. The best-performing ones are magnets for both capital and ideas, setting governance benchmarks that others must meet or exceed.

The Centre, to its credit, has encouraged this shift. Rankings on ease of doing business, startup promotion and export readiness have intensified competition in constructive ways. Investors, once daunted by India's bureaucracy, now see its regional diversity as a positive – multiple entry points, each with distinct strengths. Andhra Pradesh's ease of doing business, Punjab's entrepreneurial verve, Tamil Nadu's skilled workforce, Gujarat's infrastructure, Jharkhand's mineral base and Uttar Pradesh's vast untapped potential – each is part of a mosaic that together makes India a federation of opportunity.

Competition, of course, carries risks. It should not degenerate into a race to the bottom. States must guard against reckless subsidies or indiscriminate land giveaways that undermine fiscal stability. The smarter path lies in competing through competence and credibility, not concessions.

Healthy rivalry also fosters imitation of best practices. When one State reforms single-window clearances, others follow. When one launches an EV policy, others sharpen theirs. A Haryana success provokes a Himachal response; a Madhya Pradesh reform triggers a Chhattisgarh recalibration; an Odisha initiative spurs West Bengal to better it. This dynamic, cross-State learning is driving policy diffusion across India – a hallmark of vibrant federalism. The global manufacturing and services landscape is now in churn. As multinationals diversify away from China, they seek scale, predictability and credible governance. The "+1" in the China+1 formula must be earned – State by State. No investor lands in "India" in the abstract; they land in Bengaluru, Bhopal or Bhubaneswar. In that sense, India competes globally through its States.

The new federal compact

In just three decades, India has moved from a permission-based economy to a persuasion-based one. States no longer queue for Delhi's patronage; they campaign with CEOs and investors, pitching their case with confidence and data.

This is a transformation of mindset as much as of policy. The Andhra Pradesh-Tamil Nadu-Karnataka exchanges over Google's data centre may sound like parochial bickering, but they actually signify a maturing federal compact. States now view every investment not as central patronage but as a conquest earned through effort.

Every time Andhra Pradesh secures a tech data centre, or Gujarat wins a semiconductor plant, or Uttar Pradesh's electronics parks around Noida light up with new investment, or West Bengal breathes life into its ports and power grids to attract industry, the benefits ripple far beyond State borders. Each success strengthens supply chains, builds skills, and deepens India's industrial fabric. The bottom line: In the race for investment, every State that wins for itself, also wins for India.

> States are no longer queuing for Delhi's patronage but are campaigning with investors and pitching their case with confidence and data

GS. Paper 2 **भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था**

UPSC Mains Practice Question प्रतिस्पर्धी संघवाद भारत के आर्थिक परिवर्तन के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। अंतर-राज्यीय निवेश प्रतिद्वंद्विता में हाल के रुझानों के संदर्भ में चर्चा करें। **(150 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□□

संदर्भ:

भारत का संघीय ढांचा एक शांत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आंध्र प्रदेश में अपना सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की गूगल की योजना की हालिया घोषणा ने न केवल राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया, बल्कि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी उत्साह की लहर भी पैदा की।

- जो राजनीतिक एक-उन्नति के रूप में दिखाई दे सकता है, वह वास्तव में, जीवंत "प्रतिस्पर्धी संघवाद" का संकेत है – जहां राज्य निवेश आकर्षित करने, शासन में सुधार करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- यह भारत के पहले के "लाइसेंस-परमिट राज" युग से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित करता है, जहां निवेश निर्णयों को केंद्रीय रूप से नियंत्रित किया जाता था। आज, राज्य विकास के सक्रिय एजेंट बन गए हैं, जो भारत के समग्र आर्थिक प्रक्षेपवक्र को आकार दे रहे हैं।

पृष्ठभूमि: केंद्रीकृत योजना से प्रतिस्पर्धी संघवाद तक विकास

1991 से पहले का परिदृश्य:

- भारत ने एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का पालन किया जहां नई दिल्ली में औद्योगिक लाइसेंस, कोटा और निवेश अनुमोदन का निर्णय लिया गया।
- राज्य उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय संरक्षण पर निर्भर थे।
- इससे शासन या दक्षता के आधार पर प्रतिस्पर्धा के बजाय राजनीतिक लॉबिंग शुरू हुई।

1991 के बाद उदारीकरण:

- आर्थिक सुधारों ने औद्योगिक लाइसेंसिंग को ध्वस्त कर दिया और अर्थव्यवस्था को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया।
- पूंजी को आकर्षित करने की शक्ति केंद्र से राज्यों को हस्तांतरित की गई।
- राज्यों को अब बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, नीतिगत स्थिरता, शासन और कुशल श्रम पर प्रतिस्पर्धा करनी थी।

"अनुमति-आधारित" से "अनुनय-आधारित" अर्थव्यवस्था के इस विकास ने भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद के उदय को चिह्नित किया।

प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है?

- परिभाषा: प्रतिस्पर्धी संघवाद एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जहां सरकार के विभिन्न स्तर (मुख्य रूप से राज्य) निवेश, प्रतिभा और संसाधनों को आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे शासन में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
- यह सहकारी संघवाद का पूरक है, जहां केंद्र और राज्य राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए सहयोग करते हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

- निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण।
- राज्यों के बीच बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा।
- नीतिगत नवाचार, दक्षता और निवेशकों के विश्वास पर ध्यान दें।

उदाहरण:

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग व्यापार सुधारों के आधार पर राज्यों को सालाना रैंक देती है।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (नीति आयोग) - पिछड़े जिलों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक सुधार।

वर्तमान संदर्भ: विकास चालक के रूप में अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा

- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक वर्तमान में एआई, सेमीकंडक्टर और ईवी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- आंध्र प्रदेश में गूगल का एआई डेटा सेंटर, फॉक्सकॉन के इलेक्ट्रॉनिक हब और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच वेदांता-फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम दिखाता है कि उच्च मूल्य के निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कैसे तेज हो गई है।
- इस तरह की प्रतिद्वंद्विता ने मुख्यमंत्रियों को "नीति उद्यमियों" में बदल दिया है, जो अपने राज्यों को विश्व स्तर पर बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए पेश कर रहा है।

आर्थिक और शासन महत्व

(a) संघीय गतिशीलता को बढ़ावा

- राज्यों को शासन, बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण और नीति स्थिरता में सुधार के लिए प्रोत्साहित करता है।
- विकास की पहल के लिए केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।

(b) निवेश के माहौल को बढ़ाता है

- निवेशक अब राज्य-स्तरीय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करते हैं – उदाहरण के लिए, तमिलनाडु का कुशल कार्यबल, गुजरात का बुनियादी ढांचा, आंध्र प्रदेश की प्रशासनिक दक्षता।
- इसने पारंपरिक मेट्रो हब से परे भारत के निवेश मानचित्र में विविधता लाई है।

(c) नीतिगत नवाचार को बढ़ावा देता है

- राज्य सफल नीतियों को दोहराते हैं - उदाहरण के लिए, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, स्टार्टअप नीतियां, ईवी विनिर्माण केंद्र।
- नकल के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करता है - प्रतिद्वंद्विता का एक सकारात्मक स्पिलओवर।

(d) राष्ट्रीय विकास को मजबूत करता है

- प्रत्येक राज्य की सफलता भारत के व्यापक आर्थिक विस्तार में योगदान देती है।
- जैसा कि डॉ. सुब्बाराव कहते हैं: "हर राज्य जो अपने लिए जीतता है, वह भारत के लिए भी जीतता है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

भूक्षेत्र	उपराष्ट्रीय प्रतियोगिता का उदाहरण	परिणाम
संयुक्त राज्य अमेरिका	अमेजन के मुख्यालय 2 परियोजना की मेजबानी के लिए 200 से अधिक शहरों ने बोली लगाई।	शहरी नियोजन और स्थानीय सुधारों को बढ़ावा दिया।

भूक्षेत्र	उपराष्ट्रीय प्रतियोगिता का उदाहरण	परिणाम
जर्मनी	लैंडर बीएमडब्ल्यू, सीमेंस जैसे उच्च तकनीक उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।	बवेरिया नवाचार केंद्र के रूप में उभरा।
ऑस्ट्रेलिया	राज्य खनन और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।	क्षेत्रीय विविधीकरण को बढ़ावा देता है।
कनाडा	ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया ने तकनीक और फिल्म निवेश को आकर्षित किया।	सेवा-क्षेत्र की उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है।

इन उदाहरणों से पता चलता है कि संघों के भीतर विकेंद्रीकृत प्रतिस्पर्धा उत्पादकता और नवाचार को कैसे बढ़ा सकती है।

जोखिम और चुनौतियाँ

(ए) नीचे की ओर दौड़:

- अनियंत्रित प्रतिद्वंद्विता राजकोषीय अविवेक का कारण बन सकती है, क्योंकि राज्य निवेशकों को लुभाने के लिए अत्यधिक सब्सिडी या भूमि रियायतें प्रदान करते हैं।
- यह राज्य के वित्त को नष्ट कर सकता है और क्षेत्रीय असमानताएं पैदा कर सकता है।

(b) असमान विकास:

- बेहतर बुनियादी ढांचे वाले विकसित राज्य (जैसे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र) गरीब राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अधिक निवेश आकर्षित करना जारी रख सकते हैं।

(ग) समन्वय अंतराल:

- अत्यधिक प्रतिस्पर्धा सहकारी संघवाद को कमजोर कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय लक्ष्यों (जैसे, समान कर नीतियां, पर्यावरण मानक) को प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

केंद्र और नीति आयोग की भूमिका

- नीति आयोग की भूमिका "टीम इंडिया" दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए विकसित हुई है - सूचकांकों और रैंकिंग के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:
    - नवाचार सूचकांक
    - निर्यात तैयारी सूचकांक
    - सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक
- ये रैंकिंग न केवल राज्यों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं बल्कि साक्ष्य-आधारित शासन को भी बढ़ावा देती हैं।

इस प्रकार केंद्र का दृष्टिकोण सहयोग के साथ प्रतिस्पर्धा को संतुलित करता है – यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंद्विता सुधार की ओर ले जाती है, प्रतिगमन की नहीं।

आगे की राह

- क्षमता के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करें, रियायतों के माध्यम से नहीं: बुनियादी ढांचे, शासन और कार्यबल पर ध्यान दें, न कि कर छूट पर।
- सहकारी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना: क्षेत्रीय समूहों (जैसे, दक्षिण भारतीय तकनीकी गलियारा, पूर्वी औद्योगिक बेल्ट) पर सहयोग।
- राजकोषीय जिम्मेदारी को मजबूत करना: सब्सिडी और प्रोत्साहनों में पारदर्शिता बनाए रखें।
- सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें: अंतर-राज्यीय मंचों और नीति आयोग के मंचों को राज्यों को एक-दूसरे से सीखने में मदद करनी चाहिए।

समाप्ति

- एक केंद्रीकृत, लाइसेंस-नियंत्रित अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धी राज्यों के संघ तक भारत की यात्रा इसके विकास की गाथा में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। आज देखी गई "अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता" - चाहे वह गूगल के एआई केंद्र या फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर संयंत्र पर हो - विभाजन का संकेत नहीं है, बल्कि भारत के परिपक्व संघवाद का एक प्रमाण है।
- जैसा कि दुव्वुरी सुब्बाराव ने ठीक ही कहा है, यह प्रतिद्वंद्विता "नीति के साथ-साथ मानसिकता के परिवर्तन" का प्रतिनिधित्व करती है - जहां सुधार, नवाचार और शासन उत्कृष्टता के माध्यम से सफलता अर्जित की जाती है।
- इस दौड़ में, निवेश और नवाचार जीतने वाला प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ताकत देता है, यह साबित करता है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद भारत की विकास गाथा का नया इंजन है।